

**अतिआवश्यक/अति महत्वपूर्ण**  
**एक राष्ट्र एक चुनाव कोविंद समिति की रिपोर्ट संदर्भ**

प्रतिष्ठा में,

प्रिय महोदय/महोदया

राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय सचिव/राष्ट्रीय महामंत्री/राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष

सादर प्रणाम/नमस्कार

उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। समिति ने तीनों स्तरों की सरकारों के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है, जिससे खर्च कम हो सके, शासन में सुधार हो सके और चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके।

**मुख्य बिंदु—**

1. संविधान में संशोधनरू समिति ने संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन की सिफारिश की है।
2. दो-चरणीय प्रक्रिया लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, उसके बाद स्थानीय निकायों के चुनाव 100 दिनों के भीतर होंगे।
3. एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र समिति ने एकीकृत मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने का प्रस्ताव दिया है।
4. लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करना चुनाव आयोग को लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना बनानी होगी और अनुमान लगाना होगा।

**एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ—**

1. खर्च में कमी एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खर्च में कमी आएगी।
2. शासन में सुधार एक साथ चुनाव कराने से चुनी हुई सरकारें शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।
3. चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना एक साथ चुनाव कराने से चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।
4. निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव एक साथ चुनाव कराने से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।
5. एकता को बढ़ावा देना एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा।

**चुनौतियाँ—**

1. मध्यावधि चुनाव कराना एक साथ चुनाव कराने के लिए मध्यावधि चुनाव की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण होगा।
2. संविधान में बदलाव एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में बदलाव करना आवश्यक होगा।
3. लॉजिस्टिक चुनौतियाँ एक साथ चुनाव कराना लॉजिस्टिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा।
4. राजनीतिक सहमति एक साथ चुनाव कराने के लिए राजनीतिक सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. स्थानीय मुद्दों का महत्व कम होना एक साथ चुनाव कराने से स्थानीय मुद्दों का महत्व कम हो सकता है।

**आगे का रास्ता—**

1. व्यापक सहमतियु सरकार को सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से सहमति प्राप्त करनी होगी।
2. चुनाव आयोग की भूमिका को मजबूत करना चुनाव आयोग की निगरानी क्षमता को बढ़ाने से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।
3. इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र आईटी-सक्षम उपकरणों का उपयोग करके मतदाता पहचान पत्र की सटीकता और अखंडता में सुधार किया जा सकता है।
4. राज्य द्वारा चुनावों को वित्तपोषित करना राज्य द्वारा चुनावों को वित्तपोषित करने से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी।

**निष्कर्ष—**एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लागू करने से पहले व्यापक सहमति और विचार-विमर्श आवश्यक है।

**भवदीय**

( जटाशंकर त्रिपाठी)  
कार्यक्रम संयोजक  
स्वराज फाउंडेशन

संदर्भ—पी.एम.ओ कोविंद कमेटी रिपोर्ट

**“Inspired by Kovind Committee Powered by People, Endorsed by Leadership”**

**“For a Decisive, Transparent Bharat –Thanks to the Vision of PM Modi and shri Kovind”**

**"All communications will**

**be accepted only through**

**emel id- [chairperson@swarajfoundation.net](mailto:chairperson@swarajfoundation.net).**

**Ref – 1005**

### **One Nation One Election: Kovind Committee Report**

The High-Level Committee (HLC) has submitted its report on One Nation One Election to the President. The committee has recommended holding simultaneous elections to all three levels of government, which would reduce costs, improve governance, and streamline the election process.

#### **Key Points:**

1. Constitutional Amendments: The committee has recommended amendments to Articles 83 and 172 of the Constitution.
2. Two-Stage Process: Lok Sabha and state legislative assembly elections would be held simultaneously, followed by local body elections within 100 days.
3. Single Electoral Roll and Voter ID: The committee has proposed creating a unified electoral roll and voter ID.
4. Meeting Logistical Requirements: The Election Commission would need to plan and estimate logistical requirements.

#### **Benefits of One Nation One Election:**

1. Reduced Expenditure: Holding simultaneous elections would reduce election expenses for political parties and candidates.
2. Improved Governance: Simultaneous elections would allow elected governments to focus on governance.
3. Streamlined Election Process: Simultaneous elections would streamline the election process.
4. Fair and Transparent Elections: Simultaneous elections would ensure fair and transparent elections.
5. Promoting National Unity: Simultaneous elections would promote national unity.

#### **Challenges:**

1. Holding Mid-Term Elections: Arranging mid-term elections would be challenging.
2. Constitutional Changes: Constitutional changes would be necessary to hold simultaneous elections.
3. Logistical Challenges: Holding simultaneous elections would be logistically challenging.
4. Political Consensus: Obtaining political consensus would be necessary.
5. Local Issues May Be Overlooked: Local issues may be overlooked in simultaneous elections.

#### **Way Forward:**

1. Broad Consensus: The government would need to obtain consensus from all political parties and state governments.
2. Strengthening the Role of the Election Commission: Enhancing the Election Commission's monitoring capabilities would ensure fair and transparent elections.
3. Electronic Voter ID: Using IT-enabled tools would improve the accuracy and integrity of voter IDs.
4. State Funding of Elections: State funding of elections would ensure transparency and fairness in the election process.
5. Conclusion: Implementing the concept of One Nation One Election would require broad consensus and deliberation.

Sincerely,  
Jatashankar Tripathi  
Program Coordinator  
Swaraj Foundation

**"Reference-PMO Kovind Committee Report"**

**“Inspired by Kovind Committee Powered by People, Endorsed by Leadership”**